



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 1985/आश्विन 16, 1907

No. 478]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1985/ASVINA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1985

आदेश

का. आ. 729(अ)/18क/आई डी आर ए/85- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का. आ. 790 (अ)/ तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा यथा सशोधित आदेश स. का. आ. 734(अ)/18क/आई डी आर ए/82 तारीख 12 अक्टूबर, 1982 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) से ससे कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण उपक्रम का नवध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 तक को, जिसमें यह त. गे. भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रवध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और उक्त आदेश की अवधि, का. आ. 285(अ)/18क/आई डी आर ए/83- तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा 11 अक्टूबर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, का. आ. 725(अ)/18क/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अक्टूबर, 1983 द्वारा 11 अप्रैल, 1984 911 GI/85

तक, का. आ. 279(अ)/18क/आई डी आर ए/84, तारीख 11 अप्रैल, 1984 द्वारा 11 अक्टूबर, 1984 तक, का. आ. 786 (अ)/18क/आई डी आर ए/84 तारीख 11 अक्टूबर, 1984 द्वारा 11 अप्रैल, 1985 तक और का. आ. 300 (अ)/18क/आई डी आर ए/85- तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा 11 अक्टूबर, 1985 तक बढ़ा दी गई थी।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक, उपक्रम गुजरात राज्य वस्त्र निगम के प्रवध के अधीन 11 अप्रैल, 1986 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अप्रैल, 1986 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का. स. 3 (1)/82-सी यू. एस.]

ए. पी. सरवन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th October, 1985

ORDER

S.O. 729(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 734(E)|18AA|IDRA|82, dated the 12th October, 1982, as amended vide S.O. 790(E)|dated the 9th November, 1982 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole undertaking known as Messrs Kanti Cotton Mills Private Limited, Surendranagar, Gujarat, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of 6 months upto and inclusive of the 11th April, 1983 and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the duration of the said order was extended upto and inclusive of the 11th October, 1983 by S.O. 285(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th

April, 1983; upto 11th April, 1984, by S.O. 725(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th October, 1983; upto 11th October, 1984; by S.O. 279(E)|18AA|IDRA|84, dated the 11th April, 1984; upto 11th April, 1985, by S.O. 786(E)|18AA|IDRA|84, dated the 11th October, 1984; upto 11th October, 1985; and by S.O. 300(E)|18AA|IDRA|85, dated the 11th April, 1985;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Gujarat State Textile Corporation for a further period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 11th April, 1986.

[File No. 3(1)|82-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.